प्रकृति माँ के अनुरूप है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

04 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

लेखक-
नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

''भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमें मानव सशक्तीकरण के लिए स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है।''

कल, संयुक्त राष्ट्र ने मुझे (नरेंद्र मोदी) चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड के साथ सम्मानित किया। मैं इस सम्मान को प्राप्त करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन, यह पुरस्कार भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों के लिए है, जिन्होंने हमेशा प्रकृति को माँ के अनुरूप समझा है।

एक गर्व का क्षण-

यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस और एरिक सोलहैम द्वारा भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करने और इस संदर्भ में कार्य करने के लिए सराहना करना हर भारतीय के लिए यह एक गर्वपूर्ण क्षण था।

मनुष्य और प्रकृति का एक बहुत ही विशेष संबंध है। प्रकृतिरूपी माँ ने हमेशा हमारा पालन पोषण किया है। विदित हो कि नदियों के तट पर ही कई सभ्यताओं का निर्माण हुआ। वैसे समाज जो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं वे समृद्ध और खुशहाल होते हैं।

आज, मानव समाज एक महत्त्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। आज हम जिस मार्ग का चुनाव करेंगे वह न केवल हमारे कल्याण को निर्धारित करेगा, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी निर्धारित करेगा। हमारे लालच और आवश्यकताओं के असंतुलन ने गंभीर पारिस्थितिकीय असंतुलन को जन्म दिया है। हम या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, इन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ सकते है या हम सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

गौर किया जाये तो इस मामले में ऐसी तीन चीजें है जो यह निर्धारित करती हैं कि हम एक समाज के रूप में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं।

पहला आंतरिक चेतना है। इसके लिए, हमारे गौरवशाली अतीत की तुलना करने से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। प्रकृति का सम्मान भारतीय परंपराओं के केंद्र में है। अथर्ववेद में पृथ्वी सुक्ता है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में अद्वितीय ज्ञान शामिल हैं। यह अथर्ववेद में खूबसूरती से लिखा गया है: पृथ्वी माँ को नमस्कार है।

पूर्वजों ने पंचतत्त्व - पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि तथा आकाश बताये हैं और यह भी बताया है कि कैसे हमारे जीवन प्रणाली इन तत्त्वों के सुसंगत कामकाज पर आधारित हैं। महात्मा गांधी ने पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर लिखा और यहां तक कि एक जीवनशैली का अभ्यास किया, जहाँ पर्यावरण की ओर करुणा आवश्यक थी। उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जो वर्तमान पीढ़ी पर निर्भर करता है। उन्होंने टिकाऊ खपत के लिए बुलाया ताकि दुनिया को संसाधन की कमी का सामना न हो।

जन जागरूकता की आवश्यकता है-

दूसरा पहलू सार्वजनिक जागरूकता है। हमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर जितना संभव हो सके बात करने, लिखने, चर्चा करने और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। साथ ही, पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है। यह तब होता है जब अधिकतर लोग हमारे समय की चुनौतीपूर्ण चुनौतियों और उन्हें कम करने के तरीकों के बारे में जानेंगे।

जब हम समाज के रूप में पर्यावरण संरक्षण के साथ हमारे मजबूत संबंधों से अवगत हैं और नियमित रूप से इसके बारे में बात करते हैं, तो हम स्वचालित रूप से एक स्थायी वातावरण की दिशा में काम करने में सक्रिय होंगे। यही कारण है कि, मैं (नरेंद्र मोदी) सकारात्मक परिवर्तन लाने के तीसरे पहलू के रूप में सक्रियता रखूंगा।

इस संदर्भ में, मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत के 130 करोड़ लोग सक्रिय हैं और एक साफ और हरित पर्यावरण की दिशा में काम करने के लिए सबसे आगे हैं।

हम स्वच्छ भारत मिशन में इस सक्रियता को देखते हैं, जो सीधे एक स्थायी भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारत के लोगों के आशीर्वाद के साथ, 85 मिलियन से अधिक परिवारों के पास पहली बार शौचालयों तक पहुंच संभव हो सकी है। स्वच्छता कवरेज 39% से 95% तक है। ये हमारे प्राकृतिक परिवेश पर तनाव को कम करने की तलाश में ऐतिहासिक प्रयास हैं।

हम उज्ज्वला योजना की सफलता में इस सक्रियता को देखते हैं, जहाँ अस्वास्थ्यकर खाना पकाने के तरीकों के कारण इनडोर वायु प्रदूषण में काफी कमी आई है जिससे श्वसन रोग का निर्माण हो रहा था। आज तक, पाँच करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे महिलाओं और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ जीवन सुनिश्चित हुई है।

भारत अपनी नदियों की सफाई में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गंगा, जो भारत की जीवन रेखा है, कई हिस्सों में प्रदूषित हो गई थी। नमामि गंगे मिशन इस ऐतिहासिक अवधारणा को बदल रहा है। सीवेज के उचित उपचार पर भी जोर दिया जा रहा है।

हमारे शहरी विकास पहलों के मूल में एएमआरयूटी और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे पर्यावरणीय देखभाल के साथ शहरी विकास को संतुलित करने की आवश्यकता है। किसानों को वितरित 13 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड उन्हें यह निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं जो उनकी उत्पादकता को बढ़ावा देंगे और हमारी भूमि की उर्वरता में सुधार करेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

हमारे पास पर्यावरण क्षेत्र में कौशल भारत के एकीकृत उद्देश्य शामिल हैं और 2021 तक पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीवन और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में लगभग सात मिलियन युवाओं को स्किल करने के लिए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत योजनाएँ शुरू की गई हैं। यह कई अवसरों का निर्माण करेगी।

हमारा देश ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों पर अद्वितीय रूप से ध्यान दे रहा है। पिछले चार वर्षों में, यह क्षेत्र अधिक सुलभ और सस्ता बन गया है।

इसके अलावा, उजाला योजना के माध्यम से लगभग 31 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है। एलईडी बल्बों की लागत और साथ ही बिजली के बिलों और CO_2 उत्सर्जन में भी कमी आ गयी हैं।

भारत की सक्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है। मुझे गर्व है कि भारत 2015 में पेरिस में Cop-21 वार्ता के अग्रभाग में सबसे आगे रहा। मार्च 2018 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए कई देशों के विश्व नेता नई दिल्ली में एकत्रित हुए, जहाँ सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने और सौर ऊर्जा को सक्षम बनाने के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट किया गया।

जलवायु न्याय-

जहाँ एक तरफ दुनिया जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रही है, वही दूसरी तरफ भारत जलवायु न्याय के लिए आवाज उठा रहा है। जलवायु न्याय समाज के गरीब और सीमांत वर्गों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के बारे में है, जो अक्सर जलवायु परिवर्तन के खतरे से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।

जैसा कि मैंने (नरेंद्र मोदी) पहले भी लिखा है कि वर्तमान में किये गये हमारे कार्य मानव सभ्यता को काफी प्रभावित करेंगे।

यह अब हमारे ऊपर है कि हम एक स्थायी भविष्य के लिए वैश्विक जिम्मेदारी के बोझ को उठाएँ। विश्व को पर्यावरणीय दर्शन के प्रतिमान में बदलाव करने की जरूरत है। मैं (नरेंद्र मोदी) उन सभी व्यक्तियों और संगठनों को बधाई देना चाहता हूं जो इस दिशा में दृढ़ता से काम कर रहे हैं।

वे हमारे समाज में एक बड़े बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं (नरेंद्र मोदी) उन्हें इन कार्यों में सरकार से सभी संभव समर्थन का आश्वासन देता हूँ। साथ ही मैं (नरेंद्र मोदी) यह कहना चाहूँगा कि हम एक स्वच्छ वातावरण बनाएंगे जो मानव सशक्तीकरण का आधारशिला होगा!

* * *

क्या है पेरिस समझौता?

- यदि कम शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पेरिस समझौते में तय लक्ष्य

- पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकीकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है।
- पेरिस समझौता मूलत: मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। साथ ही, यह समझौता उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख भी करता है।
- इसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution) की सं. कल्पना को प्रस्तावित किया गया है और प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे।
- पेरिस समझौते में प्रावधान है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये गरीब देशों को 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) प्रदान करके सहायता करनी चाहिये।
- यद्यपि समझौते में रिपोर्टिंग की आवश्यकता जैसे कुछ बाध्यकारी तत्त्व हैं, परन्तु समझौते का अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना, बाध्यकारी नहीं है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है पेरिस समझौता?

- ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन से संबंधित वर्तमान प्रतिबद्धता (क्योटो प्रोटोकॉल) 2020 में समाप्त हो जाएगी। अत: पेरिस समझौते से ही तय होगा कि वर्ष 2020 के बाद क्या किया जाना चाहिये।
- भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिये समझौते में प्रावधान किया गया है कि विकसित देश अपने विकासशील समकक्षों को सालाना 100 बिलियन डॉलर देंगे।
- पेरिस समझौता भारत के लिये इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है कि यहाँ भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है।
- हालाँकि यही वे बिंदु हैं जिनका हवाला देते हुए अमेरिका खुद को पेरिस समझौते से अलग करने की घोषणा कर चुका है।

पेरिस समझौते का आलोचनात्मक पक्ष

- संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती के दावों को पूरा कर लिया जाता है तो भी, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने के लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं होगा।
- समझौते के अधिकांश प्रावधान 'वादे' तथा गैर-बाध्यकारी लक्ष्यों पर आधारित हैं, जबकि जरूरत दृढ़ प्रतिबद्धताओं की है।
- उत्सर्जन कटौती कम करने का एकमात्र जरिया देशों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution, NDC) ही है। अत: वैश्विक बाध्यकारी नियमों के बिना उत्सर्जन में कटौती एक दुष्कर कार्य होगा।
- भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Nationally Determined Contribution)।
- भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution, NDC) के तहत वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत ने वृक्षारोपण और वन क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है।
- भारत कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया (anchor of a global solar alliance) के तौर पर कार्य करेगा।

बॉन सम्मेलन

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 में 'रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन' (Rio Earth Summit) में तीन सम्मेलन स्वीकार किए गए।
- ये अभिसमय थे-जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु सम्मेलन।
- 21 मार्च, 1994 को 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (UNFCCC) प्रभावी हुआ।
- जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना यूएनएफसीसीसी का मुख्य लक्ष्य है।
- 197 देश, जिन्होंने सम्मेलन की अभिपुष्टि की है उन्हें 'सम्मेलन का पक्षकार' कहा जाता है।
- पक्षकारों का सम्मेलन यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णयन निकाय है जिसका प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. गाँधी जी के पर्यावरण संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गाँधी जी द्वारा टिकाऊ अवधारणा पर बल दिया गया।
2. ट्रस्टीशिप सिद्धातों में पर्यावरण संरक्षण मूल्य समाहित है।
3. पर्यावरण संरक्षण हेतु उन्होंने एक उपयुक्त जीवनशैली पर बल दिया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 1
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में कौन-कौन से कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में मुख्य भूमिका निभायेंगे?

1. स्वच्छ भारत मिशन
2. उज्ज्वला योजना
3. नमामि गंगे
4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1 और 3
(b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

3. पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिकीकरण से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होने दिया जायेगा।
2. इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की परिकल्पना प्रस्तुत की गई।
3. इसके तहत उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना बाध्यकारी है।
4. इसमें जलवायु वित्त (Climate Finance) की परिकल्पना की गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) 1, 2 और 4
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

नोट :

03 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(d), 3(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरणीय दर्शन के प्रतिमान को जलवायु परिवर्तन से बदलकर जलवायु न्याय करना होगा।" व्याख्या कीजिए। (250 शब्द)

For a stable future model of environmental philosophy of climate change should be replaced by climate justice." Discribe. (250 Words)